RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 180
दि. 04.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

व्हाइट हाउस में सत्ता का झटका: ट्रंप प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल से मचा सियासी भूचाल

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राजनीति इस समय एक असाधारण उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता के शीर्ष स्तर पर लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों ने न केवल प्रशासनिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके दूरगामी संकेत दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक के सबसे सख्त और निर्णायक कदम उठाते हुए महज 24 घंटे के भीतर आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल जैसे अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को हटा दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव और घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे सत्ता के भीतर एक बड़े पुनर्गठन और वफादार नेतृत्व स्थापित करने की रणनीति के तौर पर समझा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की यह शैली पहले भी चर्चा में रही है, लेकिन इस बार जिस तेजी और व्यापकता से फैसले लिए गए हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

इस सिलसिले की शुरुआत होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख क्रिस्टी नोएम को अचानक पद से हटाए जाने से हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनके हटाए जाने की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन लंबे समय से उनकी कार्यशैली और फैसलों को लेकर उठ रहे सवालों ने इस निर्णय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, ऐसे में उसके प्रमुख का इस तरह अचानक हटाया जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी बढ़ती विवादित छवि और

आलोचनाओं ने प्रशासन पर दबाव बढ़ाया, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।

इसके तुरंत बाद अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने का फैसला सामने आया, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। माना जा रहा है कि यह निर्णय चर्चित एपस्टीन मामले के प्रबंधन को लेकर उठे विवादों के कारण लिया गया। लंबे समय से इस मामले में 'क्लाइंट लिस्ट' को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस नेटवर्क में किन प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही है। जब बॉन्डी ने 'एपस्टीन फाइल्स फेज 1' के नाम से कुछ दस्तावेज जारी किए, तो उम्मीद थी कि इससे बड़े खुलासे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा, इस कदम ने विवाद को और बढ़ा दिया और प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। अंततः यह मुद्दा इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति को खुद इससे जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़े।

इसी बीच, अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी समय से पहले पद छोड़ने का आदेश दिया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्हें अचानक हटाए जाने से यह साफ संकेत मिला कि सेना के शीर्ष स्तर पर भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के कार्यभार संभालने के बाद से ही कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों में फेरबदल देखने को मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन एक नई और पूरी तरह भरोसेमंद टीम तैयार करने में जुटा है। रैंडी जॉर्ज की जगह वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर ला नेव को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पहले से ही रक्षा नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं।

इन घटनाओं के बाद अब जिन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें एफबीआई प्रमुख काश पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले पटेल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। आरोप है कि उन्होंने एफबीआई के सरकारी जेट का इस्तेमाल निजी कार्यक्रमों में जाने के लिए किया, साथ ही अपनी निजी जिंदगी से जुड़े लोगों को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई। इन आरोपों ने न केवल उनकी छवि को प्रभावित किया है, बल्कि एजेंसी की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं।

इसके अलावा, उनके नेतृत्व में एफबीआई के कई अधिकारियों को हटाए जाने का मुद्दा भी विवाद का कारण बना हुआ है। खासकर वे अधिकारी जो ट्रंप से जुड़े मामलों की जांच में शामिल थे, उनके हटाए जाने से यह आरोप लगा कि एजेंसी को राजनीतिक प्रभाव में संचालित किया जा रहा है। इस मामले ने कानूनी रूप भी ले लिया है और कुछ बर्खास्त अधिकारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व एफबीआई एजेंटों के दावों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है कि पटेल को भी जल्द हटाया जा सकता है।

दूसरी ओर, तुलसी गबार्ड का नाम भी संभावित बदलावों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। गबार्ड ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान अपने पूर्व सहयोगी का बचाव किया, जिन्होंने ईरान युद्ध का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया था। इसके अलावा उन्होंने ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर ट्रंप के दावों पर भी सवाल उठाए। यह रुख प्रशासन की आधिकारिक लाइन से अलग माना जा रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने निजी स्तर पर अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ गबार्ड को बदलने की संभावना पर चर्चा भी की है।

कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम अमेरिकी प्रशासन में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठा नेतृत्व अपनी नीतियों और रणनीतियों के अनुरूप टीम को ढालने में जुटा है। हालांकि इस तरह के तेज और व्यापक बदलाव प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी जोखिम रहता है कि इससे संस्थागत स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इस समय अमेरिका जिस तरह के वैश्विक और घरेलू दबावों का सामना कर रहा है, उसमें इस प्रकार के निर्णयों का प्रभाव केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह प्रशासनिक पुनर्गठन किस दिशा में जाता है और इसका अमेरिका की नीतियों तथा वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ता है।

पुडुचेरी में 'BEST' विज़न का शंखनाद: विकास राजनीति और जनसंपर्क का नया समीकरण

Narendra Modi ने पुडुचेरी में चुनावी माहौल के बीच विकास और जनसंपर्क की एक नई कहानी लिखने की कोशिश की, जहां उन्होंने 'BEST' मंत्र के जरिए केंद्रशासित प्रदेश के भविष्य का रोडमैप सामने रखा। यह केवल एक चुनावी भाषण नहीं था, बल्कि एक व्यापक विज़न का प्रस्तुतीकरण था, जिसमें बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म को विकास के चार मजबूत स्तंभ के रूप में परिभाषित किया गया। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पुडुचेरी को केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक पहचान वाले बहुआयामी विकास मॉडल के रूप में देख रही है।

पुडुचेरी की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री का रोड शो अंसारी दुरईसामी रोड से कामराज सलाई तक पहुंचा, तो यह केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जनता से सीधा संवाद भी था। इस दौरान उनके साथ N Rangasamy, Namassivayam और A Namassivayam Ramalingam जैसे स्थानीय नेता भी मौजूद रहे, जिससे यह संदेश गया कि केंद्र और राज्य नेतृत्व

मिलकर विकास की दिशा तय कर रहे हैं। रोड शो में उमड़ी भीड़ ने यह भी संकेत दिया कि चुनावी माहौल अपने चरम पर है और हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 'BEST' मंत्र को विस्तार देते हुए कहा कि पुडुचेरी में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने गुणवत्ता और आधुनिकता पर जोर दिया, जिससे यह क्षेत्र न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने पुडुचेरी की पहचान का अहम हिस्सा बताया, जहां आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहीं टूरिज्म को उन्होंने आर्थिक विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के कारण हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी संदर्भ में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उनका कहना था कि चुनावी सफलता का असली आधार बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, जो घर-घर जाकर लोगों से संपर्क बनाते हैं और उन्हें सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुकूल माहौल को वोट में बदलना ही असली परीक्षा है और इसमें हर कार्यकर्ता की भूमिका निर्णायक होती है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र "परिवार पहले" है, जबकि भाजपा और एनडीए "पुडुचेरी पहले और भारत पहले" के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह बयान केवल आलोचना नहीं था, बल्कि एक वैचारिक अंतर को उजागर करने की कोशिश भी थी, जिसमें विकास बनाम वंशवाद की बहस को सामने रखा गया।

पुडुचेरी की विशेषता यह है कि यहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर आधारित है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में हुए सुधारों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के साथ-साथ वीजा प्रक्रियाओं में सुधार ने विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया है।

एनसीपी में सत्ता संग्राम: पवार परिवार की राजनीति में उलझी सुनेत्रा, अंदरूनी जंग ने बढ़ाई अनिश्चितता

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित गुट) के भीतर छिड़ी वर्चस्व की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर जो असमंजस पैदा हुआ था, वह अब एक बड़े सियासी संघर्ष का रूप ले चुका है। इस संघर्ष के केंद्र में सुनेत्रा पवार हैं, जिनके सामने पार्टी के दो वरिष्ठ और अनुभवी नेता—सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल—खड़े नजर आ रहे हैं। दिलचस्प और जटिल पहलू यह है कि इस पूरे विवाद को हवा देने में विपक्षी खेमे से आने वाली एक 'गुप्त सूचना' ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल, 16 फरवरी 2026 को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया एक गोपनीय पत्र इस पूरे विवाद की जड़ बन गया है। इस पत्र में उन्होंने मांग की थी कि पार्टी के कार्याध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान सभी अधिकार दिए जाएं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह एक साधारण प्रशासनिक मांग नहीं थी, बल्कि पार्टी की वास्तविक कमान अपने हाथों में लेने की रणनीतिक कोशिश थी। इस कदम ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर एक गहरी खींचतान चल रही है। यह मामला तब और पेचीदा हो गया जब इस गुप्त पत्र की जानकारी राकांपा (शरद गुट) के विधायक रोहित पवार तक पहुंच गई। बताया जाता है कि उन्हें यह सूचना अजित गुट के ही एक नेता ने दी, जिसके बाद उन्होंने बिना देर किए यह बात सुनेत्रा पवार तक पहुंचा दी। यही वह क्षण था, जहां से इस राजनीतिक संघर्ष ने निर्णायक मोड़ लिया। सुनेत्रा पवार ने 10 मार्च को चुनाव आयोग को एक अलग पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि 16 फरवरी वाले पत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाए। इस कदम ने पार्टी के भीतर दो स्पष्ट धड़े बना दिए और टकराव खुलकर सामने आ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक तक देखने को मिली। प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे और कोषाध्यक्ष शिवाजीराव गर्जे के बीच हुई बहस ने यह साफ कर दिया कि मामला केवल कागजी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और राजनीतिक अविश्वास की गहराई तक पहुंच चुका है। तटकरे ने आरोप लगाया कि गर्जे विधायकों को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि गर्जे पर यह जिम्मेदारी होने की बात कही जा रही है कि वे पार्टी के फैसलों की जानकारी विधायकों तक पहुंचाएं। इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर 'निगरानी' और 'जासूसी' जैसे शब्दों को भी चर्चा में ला दिया है, जो किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए गंभीर संकेत होते हैं। इस जटिल सियासी समीकरण में पार्थ पवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने ही गर्जे को यह जिम्मेदारी दी थी कि वे तटकरे और पटेल के फैसलों पर नजर रखें और विधायकों को उसकी जानकारी दें। यह कदम तटकरे को बिल्कुल रास नहीं आया और यही वजह रही कि विवाद और गहरा गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर भरोसे का संकट गहराता जा रहा है, जहां नेता एक-दूसरे की नीयत और कदमों पर संदेह कर रहे हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और विडंबनापूर्ण मोड़ तब आया जब सुनेत्रा पवार का उठाया गया कदम ही उनके लिए 'सेल्फ-गोल' बनता नजर आने लगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि चुनाव आयोग सुनेत्रा के पत्र को स्वीकार कर लेता है और 16 फरवरी के पत्र को अमान्य कर देता है, तो इसका असर केवल तटकरे और पटेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सुनेत्रा की अपनी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर सकता है। दरअसल, प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने से जुड़े दस्तावेज और कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी 28 जनवरी के बाद चुनाव आयोग को सौंपी थी। ऐसे में यदि उस समयावधि के बाद की प्रक्रियाओं को अमान्य किया जाता है, तो तकनीकी रूप से उनकी नियुक्ति भी रद्द हो सकती है। इस विवाद का सबसे बड़ा असर पार्थ पवार पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए जो 'एबी फॉर्म' दाखिल किया है, उस पर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के हस्ताक्षर हैं। चूंकि यह प्रक्रिया भी 28 जनवरी के बाद पूरी हुई है, इसलिए यदि चुनाव आयोग सुनेत्रा के पत्र के आधार पर निर्णय लेता है, तो पार्थ का नामांकन भी अवैध घोषित किया जा सकता है। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि पूरे गुट की राजनीतिक रणनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि तटकरे और पटेल ने कानूनी प्रक्रियाओं को इस तरह उलझाया है कि सुनेत्रा पवार चाहकर भी उन्हें आसानी से दरकिनार न कर सकें। यदि यह बात सही है, तो यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीतिक खेल का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें हर कदम सोच-समझकर उठाया गया है। कुल मिलाकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस आंतरिक संघर्ष ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर अस्थिरता की ओर धकेल दिया है।

बाल कैंसर का बढ़ता संकट: भारत में हर साल 17 हजार मौतें, वैश्विक असमानताओं की कठोर सच्चाई

भारत में बाल स्वास्थ्य से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जिसने चिकित्सा जगत, नीति निर्माताओं और समाज को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका The Lancet में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में लगभग 17 हजार बच्चों की मौत कैंसर के कारण हुई, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के टूटते सपनों और अधूरी जिंदगियों की कहानी बयां करता है। इस सूची में भारत के बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जहां 16 हजार बच्चों की मौत दर्ज की गई, जबकि नाइजीरिया और पाकिस्तान में यह आंकड़ा करीब नौ-नौ हजार रहा।

अगर वैश्विक स्तर पर इस अध्ययन के निष्कर्षों को देखें, तो स्थिति एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण संकेत देती है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में बच्चों में कैंसर के लगभग 3.77 लाख नए मामले सामने आए, जिनमें से करीब 1.44 लाख बच्चों की जान चली गई। हालांकि, एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि 1990 की तुलना में वैश्विक स्तर पर बाल कैंसर से होने वाली मौतों में लगभग 27 प्रतिशत की कमी आई है। लेकिन यह राहत अधूरी है, क्योंकि इसी अवधि में अफ्रीकी देशों में बाल कैंसर से मृत्यु दर में 55.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जो वैश्विक स्वास्थ्य असमानताओं की गंभीरता को उजागर करती है।

इस पूरे परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया

गया है कि बाल कैंसर के 85 प्रतिशत नए मामले और इससे होने वाली 94 प्रतिशत मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। भारत भी इसी श्रेणी में आता है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच, समय पर जांच और आधुनिक उपचार सुविधाओं की कमी कई बार बच्चों की जान बचाने में बाधा बन जाती है। बड़े शहरों में जहां उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अब भी जागरूकता और संसाधनों की भारी कमी है।

बाल कैंसर के प्रकारों की बात करें तो सबसे अधिक मौतें Leukemia यानी ब्लड कैंसर के कारण होती हैं, जिससे हर साल करीब 45,900 बच्चों की जान जाती है। इसके बाद मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़े कैंसर और लसीका तंत्र के कैंसर प्रमुख कारण हैं। इन बीमारियों का इलाज संभव है, खासकर अगर समय पर पहचान हो जाए, लेकिन समस्या यह है कि कई मामलों में बीमारी का पता बहुत देर से चलता है, जब उपचार की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं।

इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका Lisa Force ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कैंसर नियंत्रण प्रणालियों में व्यापक निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि यदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शुरुआती पहचान, स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधाओं को मजबूत किया जाए, तो हजारों बच्चों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही, स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और दवाओं की पहुंच को भी बेहतर बनाना बेहद जरूरी है।

भारत के संदर्भ में देखें तो पिछले कुछ वर्षों में सरकार और निजी क्षेत्र ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में कई पहलें की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खासकर बाल कैंसर के मामले में एक समर्पित और व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें जागरूकता अभियान, स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य जांच, और गरीब परिवारों के लिए सस्ती या मुफ्त उपचार सुविधाएं शामिल हों। इसके अलावा, सामाजिक स्तर पर भी इस विषय को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए।

यह भी समझना जरूरी है कि बाल कैंसर केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। जब किसी परिवार का बच्चा इस बीमारी से जूझता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है—मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से। कई बार इलाज की लागत इतनी अधिक होती है कि परिवार कर्ज में डूब जाता है या इलाज अधूरा छोड़ने को मजबूर हो जाता है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर रही है। यदि वैश्विक स्तर पर समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं, तो बाल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से होने वाली मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अंततः, यह समय केवल चिंता व्यक्त करने का नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का है। सरकार, चिकित्सा संस्थान, सामाजिक संगठन और आम नागरिक—सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि आने वाले वर्षों में यह आंकड़े घटें और हर बच्चे को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का अधिकार मिल सके।

संपादकीय

गिरावट रोकने को केंद्रीय बैंक बदले

पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से मजबूत मुद्रा भंडार होने के बावजूद रुपये पर दबाव होना, देश के सामने कई तरह मुश्किलें पैदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि भारत फिर 2013 जैसी स्थितियों से रूबरू है। लेकिन इस बार जहां मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति 2013 के मुकाबले मजबूत है। दरअसल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक डॉलर को मजबूत निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रूपये जैसी दूसरी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। इसकी एक वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी है। जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्राओं पर पड़ता है। यही वजह है कि एशिया में बेहद कमजोर स्थिति वाली मुद्राओं में रुपये भी शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक हकीकत यह भी है कि ईरान व अमेरिका के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। इसकी एक विसंगति यह भी है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। जिसका प्रतिशत 85 फीसदी के करीब है। फलतः तेल कंपनियां अधिक डॉलर की मांग कर रही हैं,जिसका असर रूपये की सेहत पर भी पड़ रहा है। लेकिन पिछले एक साल में रुपये के मूल्य में दस फीसदी गिरावट और डॉलर के मुकाबले उसका सर्वकालिक निम्न स्तर तक पहुचना हमारी गंभीर चिंता का विषय होना ही चाहिए। आशंका जतायी जा रही है कि यदि ईरान व अमेरिका का युद्ध और लंबा खिंचता है तो रूपये के मूल्य में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, अपनी तरफ से देश के केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक व रणनीतिक उपायों से रुपये की गिरावट को थमाने के प्रयास किए हैं, लेकिन उसका सीमित प्रभाव ही रहा है। भले ही भारत के पास सात सौ अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार हो, लेकिन उसका भी सीमित उपयोग ही रुपये के संरक्षण में हो सकता है। हालांकि, भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार है कि दस महीने के आयात को सहजता से संचालित किया जा सकता है। वास्तव में वैश्विक परिदृश्य में जारी उथल-पुथल से बाधित आर्थिकी और असुरक्षा के चलते डॉलर की बढ़ती मांग ने रूपये को कमजोर बनाया है। इसके बावजूद केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से ही रुपये का गिरना संभल सकता है। केंद्रीय बैंक तेल कंपनियों के डॉलर के अतिरिक्त दबाव को कम करने को कदम उठा सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तेल कंपनियों के लिये अलग डॉलर विंडो बनाये जाने से रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। हर दिन तेल कंपनियों को भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है। यही मांग बाजार में रुपये पर अतिरिक्त दबाव बना रही है। रिपोर्ट में एक सुझाव है कि इन कंपनियों के लिए अलग डॉलर विंडो बनाई जाए। अगर ऐसा होता है, तो बाजार में डॉलर की असली मांग और सप्लाई साफ दिखेगी। इससे रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम भी हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि रुपये को 'शॉक एब्जॉर्बर' बनाकर हर दबाव को झेलने के लिये छोड़ देने की नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि इस दिशा में केंद्रीय बैंक को आक्रमक रणनीति अपनानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रुपये को संबल देने में करना चाहिए। इसके जरिये टाले जा सकने वाली गिरावट रोकी जा सकती है। इसके लिये अर्थव्यवस्था में नकदी संतुलन भी जरूरी है। बाजार की स्थिरता के लिये ब्याज दरों का संतुलन भी लाभप्रद हो सकता है। जिससे रुपये के कमजोर होने का दबाव अर्थव्यवस्था पर न पड़े।

अंतरिक्ष अनुसंधान में अमेरिका को चीन की चुनौती

> "चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर इस बात के आसार बन रहे हैं कि स्पेस साइंस में अब अमेरिका के साथ चीन बराबरी के स्तर पर आने की होड़ में है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' इन दिनों अपने समानव चंद्र मिशन, आर्टेमिस-2 की तैयारी कर रही है, और अगले कुछ दिनों में किसी भी दिन इसका प्रक्षेपण हो जाएगा। इसमें चार यात्री जाएंगे, जो चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे। उधर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) को उम्मीद है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार देगी। चीन पहले ही कई रोबोट चंद्रमा पर भेज चुका है और चंद्र नमूने वापस ला चुका है।

चीन इस साल अपने नए मेंगझोऊ (ड्रीम शिप) अंतरिक्ष यान की परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। संभव है कि चंद्रमा पर अमेरिकी यात्री पहले उतर जाए, पर इस बात के आसार बन रहे हैं कि स्पेस साइंस में अब अमेरिका के साथ चीन बराबरी के स्तर पर आने की होड़ में है।

अभी इसे बराबरी कहना आसान नहीं है, पर एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमें वह अमेरिका के बराबर आ गया है या कुछ आगे निकल गया है। वह है स्पेस नेवीगेशन। चीन के 'बेइदू' ने अमेरिकी 'जीपीएस' को पीछे कर दिया है। इस बात को अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। चीन को उम्मीद है कि वह 2035 तक चंद्रमा पर समानव वैज्ञानिक बेस का एक बुनियादी संस्करण तैयार कर लेगा, जिसे इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन (आईएलआरएस) कहा जाएगा। यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा, जहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना है। इस परियोजना में रूस भी चीन के साथ है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने लगभग 20 अरब डॉलर की लागत से चंद्रमा पर एक बेस बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके विपरीत, नासा का आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम लगातार पिछड़ रहा है। आर्टेमिस-2 समानव फ्लाई-बाय यान है, लैंडिंग क्राफ्ट नहीं। कई बार स्थगित होने के

बाद अप्रैल, 2026 में इसका प्रक्षेपण तय है। पहली अमेरिकी मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग को आर्टेमिस-4 तक टाल दिया गया है, जो 2028 से पहले संभव नहीं। चीन का कार्यक्रम, जो तीन दशकों से अधिक समय से एक एकीकृत योजना पर आधारित है, काफी हद तक उस राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता रहा है, जो अमेरिका में चल रही है।

चीन का समानव प्रोजेक्ट 921, सितंबर, 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2003 में चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई की पहली उड़ान के बाद से लगभग 15 मानवयुक्त मिशन संचालित किए जा चुके हैं। वर्ष 2011 में अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में चीन को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन ने अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया और वह बना लिया। तियांगोंग, 2021 से काम कर रहा है और इसमें इस समय तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं। चीन के किसी भी मानवयुक्त प्रक्षेपण में कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है।

चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दो सत्रों में विमानन और अंतरिक्ष उद्योग को 'स्तंभ उद्योग' का दर्जा दिया है। पहले यह विषय उभरते हुए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था। पहली बार, 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-30) में स्पष्ट रूप से 2030 तक चीन को एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पांच वर्षीय योजना में पुनरोपयोगी प्रक्षेपण यानों, बड़े पैमाने पर उपग्रह समूहों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें लागत में कमी को दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए केंद्रीय माना गया है। एक नया 'स्पेस+' दृष्टिकोण बताता है कि उपग्रह अवसंरचना को व्यापक औद्योगिक प्रणाली के हिस्से के रूप में माना जा रहा है, जिसमें केवल संचार के बजाय पृथ्वी की कक्षा के कंप्यूटिंग उपयोग को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।

इस लिहाज से यह साल अमेरिका और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चीनी रॉकेट अमेरिकी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन फैल्कन 9 का पहला चरण नियमित रूप से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, और कुछ बूस्टर अब तक 30 बार तक उपयोग में लाए जा चुके हैं। इससे आंतरिक लागत डिस्पोज़ेबल रॉकेट की तुलना में कहीं कम हो जाती है।

नेविगेशन के क्षेत्र में, चीन ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है, जो अमेरिका के जीपीएस के बराबर या उससे भी बेहतर है। सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में, यह स्टारलिंक से कई साल पीछे है, जबकि सबसे मुश्किल काम, हजारों सैटेलाइटों को किफायती लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में, वह पीछे है। नेविगेशन सैटेलाइट इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि कुछ दर्जन सैटेलाइट ही पूरी दुनिया को कवर कर सकती हैं, जबकि इंटरनेट नेटवर्क को उपयोगी कवरेज प्रदान करने के लिए हजारों निचली कक्षा के सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है। चीन के पास अभी इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्षमता नहीं है।

बेइदू, अमेरिकी जीपीएस से अधिक उपग्रहों का संचालन करता है। अमेरिकी सरकार के नेविगेशन सलाहकार बोर्ड ने 2023 में स्वीकार किया था कि जीपीएस पिछड़ गया है। आम उपयोगकर्ताओं के लिए, अंतर मामूली है, लेकिन बेइदू की बढ़त महत्वपूर्ण है। चीन के भीतर यह सेंटीमीटर स्तर की सटीकता तक पहुंचता है। चीन ग्लोबल साउथ के देशों में बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में निवेश के साथ-साथ बेइदू प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए डिफॉल्ट नेविगेशन बुनियादी ढांचे के रूप में स्थापित किया जा सके।

सैटेलाइट इंटरनेट में चीन अभी पीछे है। स्टारलिंक के पास लगभग 8,000 उपग्रह हैं, जो स्पेसएक्स से लगभग 35 गुना अधिक हैं। ये पहले से ही 100 से अधिक देशों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। चीन के पास कुछ सौ उपग्रहों का वैश्विक नेटवर्क है, जो मुकाबला नहीं कर सकता। स्टारलिंक को इस बाज़ार में बड़ी और लगातार बढ़ती बढ़त हासिल है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ग्लोबल साउथ के उन क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड सेवा जहां इसकी पहुंच कम है, चीनी नेटवर्क भविष्य में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बराबरी की कवरेज प्रदान करने में कई साल लगेंगे।

बहरहाल, चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ उपलब्धियों पर नज़र डालें, तो आप मानेंगे कि वह अमेरिका को देर-सवेर पकड़ लेगा। स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग, 2021-2022 में तीन मॉड्यूल लॉन्च करके पूरा किया गया। यह लगातार चालू है और इसमें ताइकोनॉट्स छह महीने या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं। ताइकोनॉट्स चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया नाम है।

वर्ष 2025 में चीन ने 92-93 ऑर्बिटल लॉन्च किए, जो उसका राष्ट्रीय रेकॉर्ड है। इसमें लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट मुख्य हैं। लॉन्ग मार्च सीरीज 5, 7, 10 जैसे भारी रॉकेट विकसित कर रहा है, जो चंद्रमा मिशनों के लिए जरूरी हैं। चंद्रमा अन्वेषण (चैंग कार्यक्रम): चैंग-4 ने 2019 में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर भेजा।

चैंग-5 2020 में चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आया (पहली बार 44 साल बाद कोई देश ऐसा कर सका)। चैंग-6 ने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से दुनिया का पहला सैंपल रिटर्न मिशन पूरा किया। इस साल चैंग-7 की उड़ान प्रस्तावित है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ और संसाधनों की खोज करेगा। इसके बाद 2028 में चैंग-8 चंद्रमा पर बेस निर्माण की टेस्टिंग करेगा।

प्रेरणा

समय अनुशासन का मौन शिक्षक

मनुष्य के जीवन में समय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। यह एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है, जिसे न तो संचित किया जा सकता है और न ही किसी से उधार लिया जा सकता है। समय निरंतर बहता रहता है, बिल्कुल एक शांत नदी की तरह, जो किसी के लिए नहीं रुकती। जीवन की सफलता, असफलता, उपलब्धियां और संघर्ष—सब कुछ समय के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है, वह जीवन के रहस्यों को भी समझने लगता है। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, बल्कि यह हमारे कर्म, विचार और निर्णयों में भी प्रवाहित होता है।

समय का महत्व केवल बड़े-बड़े सिद्धांतों में ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे व्यवहारों में भी दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति समय पर अपने कार्यों को पूरा करता है, तो वह न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाता है, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान भी प्रकट करता है। समय की पाबंदी एक ऐसा गुण है, जो व्यक्ति को विश्वसनीय, अनुशासित और प्रभावशाली बनाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति समय की उपेक्षा करता है, वह धीरे-धीरे अपने जीवन में अव्यवस्था और असफलता को आमंत्रित करता है।

समय के प्रति इस गहरी समझ का एक प्रेरणादायक उदाहरण हमें एक महान शिक्षाविद के जीवन से मिलता है। वे न केवल अपने ज्ञान और पद के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने अनुशासन और समय-निष्ठा के लिए भी जाने जाते थे। उनके लिए समय का पालन कोई औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का मूल सिद्धांत था। एक बार उन्हें एक साहित्यिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आयोजकों से यह निवेदन किया कि उन्हें समय से पहले लेने के लिए कोई व्यक्ति भेजा जाए, ताकि वे कार्यक्रम में समय पर पहुंच सकें।

यह निवेदन उनके व्यक्तित्व की गंभीरता को दर्शाता है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी कारण से कार्यक्रम में देरी न हो। कार्यक्रम के दिन वे पूरी तैयारी के साथ समय पर तैयार होकर बैठ गए। यह दृश्य यह दर्शाता है कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग थे। वे न केवल अपने समय का सम्मान कर रहे थे, बल्कि कार्यक्रम के महत्व को भी समझ रहे थे। किन्तु दुर्भाग्यवश, उन्हें लेने आने वाला व्यक्ति निर्धारित समय से बहुत देर से पहुंचा।

जब वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा, तो उसने अपनी देरी के लिए क्षमा मांगी और अनेक कारण बताए। सामान्यतः ऐसी स्थिति में लोग परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ जाते हैं, किन्तु इस महान व्यक्ति ने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। यह निर्णय केवल एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि उनके सिद्धांतों का प्रतिबिंब था। जब उस व्यक्ति ने उनसे विनती की कि उनके न जाने से कार्यक्रम पूरी तरह बिगड़ जाएगा, तब उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उन्हें कार्यक्रम के असफल होने का दुख अवश्य होगा, किन्तु वे स्वयं को देर से पहुंचने वाला व्यक्ति कहलवाना स्वीकार नहीं कर सकते।

यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। यह सिखाती है कि समय की पाबंदी केवल व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि यह एक नैतिक मूल्य है। जब हम किसी कार्यक्रम में देर से पहुंचते हैं, तो हम केवल अपनी छवि को ही नहीं, बल्कि उस आयोजन के महत्व को भी कम कर देते हैं। समय का पालन करना दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें समाज में एक अलग पहचान दिलाता है।

आज के युग में, जहां हर व्यक्ति व्यस्तता का हवाला देकर समय की अनदेखी करता है, वहां इस प्रकार के उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि थोड़ी-सी देरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही छोटी-छोटी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। समय की उपेक्षा धीरे-धीरे एक आदत बन जाती है और फिर यह हमारे हर कार्य में दिखाई देने लगती है।

समय का सदुपयोग करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है और इसे व्यर्थ गंवाना हमारे अपने भविष्य के साथ अन्याय करना है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे अपने जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बना लेते हैं।

इस प्रेरक घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में सिद्धांतों का कितना महत्व है। यदि हम अपने मूल्यों के साथ समझौता कर लेते हैं, तो हम धीरे-धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। उस महान शिक्षाविद ने यह सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। उनका यह निर्णय भले ही उस समय कठोर लगा हो, किन्तु यह एक गहरी सीख देने वाला था।

समय हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर क्षण एक नया अवसर है। यदि हम समय के साथ चलना सीख लें, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करने के समान है, क्योंकि हमारा जीवन भी समय का ही एक रूप है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि समय केवल एक माप नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। यह हमें अनुशासन, धैर्य और कर्मठता का पाठ पढ़ाता है। जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार की प्रेरणादायक घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि समय का पालन करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक महान गुण है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करता है।

विवाह संस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच नई खाई

आधुनिकता के संक्रमणकालीन दौर में सबसे अधिक यदि कोई संस्था प्रश्नों के घेरे में है, तो वह विवाह और रिश्तों की पारंपरिक अवधारणा है। बदलती जीवनशैली, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीक, वैश्वीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चेतना ने रिश्तों की परिभाषा, अपेक्षाएँ और संरचना- सब कुछ बदल दिया है। यही कारण है कि आज रिश्तों से जुड़े प्रश्न केवल सामाजिक विमर्श का विषय नहीं रहे, बल्कि अदालतों तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच उत्पन्न हो रही नाजुक खाई को उजागर किया है। एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना लिव-इन रिलेशनशिप, भले ही एक साथी विवाहित हो, अपराध नहीं है; वहीं दूसरे मामले में न्यायालय ने ऐसे ही एक जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर पति या पत्नी के कानूनी अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। यह विरोधाभास वास्तव में न्यायिक असंगति से अधिक एक कानूनी रिक्तता और सामाजिक संक्रमण का संकेत है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमें मौजूदा परिदृश्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। निश्चित ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी के दायरे में न्यायालयों ने समय-समय पर लिव-इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर माना है। लेकिन दूसरी ओर, भारतीय कानून विवाह को एक कानूनी और सामाजिक संस्था के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसमें अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। यही वह बिंदु है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। न्यायालय लिव-इन संबंधों को अपराध नहीं मानता, परंतु उनके सभी परिणामों को वैध मानने में संकोच करता है। यह स्थिति न केवल कानूनी भ्रम उत्पन्न करती है, बल्कि सामाजिक असुरक्षा भी पैदा करती है। वास्तव में समस्या न्यायिक निर्णयों की नहीं, बल्कि स्पष्ट विधायी ढाँचे की कमी की है। यदि व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय समाज इस समय एक बड़े संक्रमणकाल से गुजर रहा है। एक ओर सदियों से स्थापित पारंपरिक जीवन मूल्य हैं, जिनमें विवाह केवल एक अनुबंध नहीं बल्कि एक संस्कार, सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक व्यवस्था का आधार है; दूसरी ओर आधुनिक जीवन की वास्तविकता है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म-विकास, करियर, आर्थिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत संतुष्टि को भी समान महत्व दिया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने रिश्तों की शक्ति-संतुलन व्यवस्था को बदल दिया है। अब रिश्ते केवल सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि आपसी समझ और संतुष्टि के आधार पर टिके रहते हैं। परिणामस्वरूप, रिश्तों की स्थायित्व की अवधारणा बदल रही है और प्रतिबद्धता अब आजीवन वचन से अधिक एक निरंतर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया बनती जा रही है।

पिछली पीढ़ियों में विवाह जीवन का अनिवार्य चरण माना जाता था। हमारे माता-पिता और दादा-दादी के लिए विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संबंध था और जीवन भर साथ निभाना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को अलग दृष्टि से देख रही है। आज के युवा पहले शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद रिश्तों के बारे में निर्णय लेते हैं। कुछ लोग विवाह से पहले साथ रहने का विकल्प चुनते हैं, कुछ रिश्तों को नाम देने से भी बचते हैं और कुछ लोग विवाह के बजाय साझेदारी को अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को महत्व नहीं देती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे रिश्तों में स्वतंत्रता, सम्मान, संवाद और समानता को अधिक महत्व देते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा परिवर्तन लिंग भूमिकाओं के बदलाव से भी आया है। पहले पुरुष कमाने वाला और महिला घर संभालने वाली मानी जाती थी, लेकिन आज दोनों काम करते हैं, दोनों निर्णय लेते हैं और दोनों भावनात्मक सहयोग चाहते हैं। आधुनिक रिश्तों में समानता, खुलकर संवाद और साझा जिम्मेदारियों पर जोर है। हालांकि पुरुष और महिलाओं की अपेक्षाएँ पूरी तरह समान नहीं होतीं-अक्सर महिलाएँ भावनात्मक सहयोग और संवाद को अधिक महत्व देती हैं, जबकि पुरुष स्वतंत्रता और बौद्धिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन इन अंतरों को समझकर ही मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं।

आज आत्म-प्रेम और आत्म-देखभाल को स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार माना जाने लगा है। तकनीक और सोशल मीडिया ने भी रिश्तों की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ तुलना की संस्कृति भी बढ़ी है। अब लोग अपने रिश्तों की तुलना दूसरों की ऑनलाइन तस्वीरों और पोस्ट से करने लगे हैं, जिससे असंतोष और अवास्तविक अपेक्षाएँ बढ़ती हैं। कई बार डिजिटल दुनिया में मिलने वाला ध्यान वास्तविक रिश्तों की आत्मीयता को कम कर देता है। ऑनलाइन फ्लर्टिंग, डिजिटल बेवफाई और लगातार उपलब्ध रहने की अपेक्षा जैसी नई समस्याएँ भी सामने आई हैं। इसलिए आज डिजिटल सीमाएँ भी उतनी ही आवश्यक हो गई हैं जितनी व्यक्तिगत सीमाएँ। ऑनलाइन डेटिंग ने रिश्तों की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। जीवनसाथी ढूँढना पहले परिवार, समाज या परिचितों के माध्यम से होता था, लेकिन अब मोबाइल एप और वेबसाइटों के माध्यम से लोग साथी ढूँढते हैं। इससे विकल्प बढ़े हैं, लेकिन साथ ही रिश्तों की स्थिरता कम हुई है।

अभियान

सनातन धर्म के 18 महापुराण: दिव्य ज्ञान का अनंत स्रोत

सनातन धर्म की विशाल और गहन परंपरा में वेदों के बाद यदि किसी ग्रंथ को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है, तो वह हैं महापुराण। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को समझाने वाले दिव्य ज्ञान के स्रोत हैं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक का वर्णन मिलता है, साथ ही धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को अत्यंत सरल और कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। महापुराणों की विशेषता यह है कि ये केवल दार्शनिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन जीने की कला, नैतिकता, कर्तव्य और आध्यात्मिक उन्नति का संपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है।

महापुराणों की संख्या अठारह मानी गई है और प्रत्येक पुराण का अपना विशेष महत्व और उद्देश्य है। इन ग्रंथों की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जिन्होंने वेदों के गूढ़ ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए पुराणों की रचना की। इन पुराणों में देवताओं की महिमा, ऋषि-मुनियों की कथाएं, राजाओं के इतिहास, तीर्थों का महत्व और जीवन के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। यही कारण है कि इन्हें भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम कहा जाता है।

अठारह महापुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण शामिल हैं। इन सभी पुराणों में अलग-अलग दृष्टिकोण से जीवन और सृष्टि का विश्लेषण किया गया है, जिससे मनुष्य को अपने अस्तित्व और उद्देश्य को समझने में सहायता मिलती है।

इन पुराणों में वर्णित कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, भागवत पुराण में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के माध्यम से भक्ति और प्रेम का महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और उनके तत्त्व का वर्णन है, जो हमें यह सिखाता है कि सृजन और संहार दोनों जीवन के आवश्यक अंग हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का संदेश मिलता है।

महापुराणों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ हमें यह समझाते हैं कि ब्रह्मांड एक चक्र के रूप में चलता है, जिसमें सृष्टि का निर्माण होता है, वह विकसित होती है और अंततः प्रलय में विलीन हो जाती है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है, और हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

इन पुराणों में धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक कर्म में निहित है। धर्म का पालन करना अर्थात अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना। महापुराण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वही है, जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। इसमें दया, करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों को अत्यंत महत्व दिया गया है।

भक्ति का महत्व भी महापुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। ये ग्रंथ हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भाव है, जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागकर पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसे सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है।

महापुराणों में कर्म के सिद्धांत का भी गहन विश्लेषण किया गया है। यह सिद्धांत बताता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, जो व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यही कर्म सिद्धांत जीवन को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाता है।

इन ग्रंथों में वर्णित कथाएं और शिक्षाएं आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी प्राचीन काल में थीं। आज जब मनुष्य भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तब महापुराणों का अध्ययन उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। ये ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।

महापुराणों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनमें जीवन के चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—का संतुलन बताया गया है। ये चारों तत्व जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाते हैं। धर्म हमें सही मार्ग दिखाता है, अर्थ जीवन के भौतिक पक्ष को संभालता है, काम हमारी इच्छाओं को संतुलित करता है और मोक्ष हमें अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। महापुराण हमें यह सिखाते हैं कि इन चारों का संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। इन पुराणों का अध्ययन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्म-चिंतन और आत्म-विकास का माध्यम भी है। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य, कर्तव्यों और मूल्यों का बोध होता है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं, हमारा जीवन क्यों है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के 18 महापुराण केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन करने वाले दिव्य दीपक हैं। इनमें निहित ज्ञान समय और स्थान की सीमाओं से परे है और हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति इन पुराणों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वह न केवल एक बेहतर इंसान बनता है, बल्कि वह आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। यही कारण है कि महापुराणों को सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर माना जाता है, जो आज भी हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

नकली बाबा और अंधविश्वास: राजनीतिक छत्रछाया में महिलाओं के शोषण की वास्तविकता

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत में, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वाले अंधविश्वासों का शिकार अक्सर महिलाएं ही होती हैं। एक तरफ हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य महाराज जैसे बाबाओं ने महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करके उसी धर्म को बदनाम किया है। मदर राम रहीम जैसे लोगों ने महिलाओं के साथ व्यभिचार करके कई महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है। यहां तक कि एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में जेल की सलाखों को गिनना भी शुरू कर दिया है। हमारे देश में ऐसे बाबा और बापू की दुकानें इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? इसका कारण हमारे उन नेताओं और राजनीतिज्ञों का संरक्षण है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इन राजनीतिज्ञों के समर्थन से, जैसे ही सरकारी चरागाह बाबाओं और बापूओं को मुफ्त में दिए जाते हैं, उनके अनुयायियों द्वारा आलीशान एसी आश्रम स्थापित कर दिए जाते हैं। और फिर वे उनमें महिलाओं के साथ विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसे बाबा फिर आलीशान कारों, चार्टर्ड विमानों, ब्रांडेड टीवी, ब्रांडेड मोबाइल जैसी सभी सांसारिक सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं और सनातन धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं तथा समाज का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। धर्म में उच्च पद पर आसीन रामभद्राचार्य जी ने महिलाओं के बारे में कहा कि महिलाएं मनोरंजन का साधन हैं। सनातन धर्म के लिए यह कितना शर्मनाक है कि एक तथाकथित गुरु के मुख से ऐसी अभद्र टिप्पणी निकले? शंकराचार्य जी के ऐसे कथन महिलाओं के मान-सम्मान को कितनी गहराई से आहत करते हैं? ऐसे निम्न स्तर की और भद्दी टिप्पणियां करने वाले लोग इसे कब समझेंगे?

यह लेखक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती देता है कि यदि आप भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं, तो भविष्य देखने वालों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब उनके शिष्यों द्वारा निर्मित विशाल गुंबदों में लाखों की भीड़ जमा हुई और उनमें कथा प्रवचन दिए गए, यदि आप उनका भविष्य जान लेते, तो भगदड़ में इतने निर्दोष लोग नहीं मरते। मेरे प्रश्नों के केवल तीन सही उत्तर दीजिए। इसके साथ ही, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई भविष्य के द्रष्टाओं को भी चुनौती है कि मैं अपने माध्यम से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ और यदि आप उनका सही उत्तर देते हैं, तो मैं अपना घर, परिवार और संसार छोड़कर जीवन भर आपके आश्रम की सेवा करूँगा। यह मेरा वादा है। और यह मेरा खुला निमंत्रण है। यह मेरा मोबाइल नंबर 9925041145 है। यदि आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आपको अपना आडंबर त्यागना होगा, अपने एसी आश्रम बंद करने होंगे, बड़ी विलासितापूर्ण कारों, हेलीकॉप्टरों और चार्टर्ड विमानों का त्याग करना होगा, और यहाँ तक कि भौतिक सुख और धन का भी त्याग करके एक आम इंसान बनना होगा। एक तरफ, जब आप अतीत, भविष्य और वर्तमान को देखने की बात करते हैं, तो आप यह क्यों नहीं देख सकते कि आप पर कौन और कब हमला करेगा? आपकी मृत्यु कब होगी? यदि आप जानते हैं, तो सरकारी या निजी खर्च पर सुरक्षा गार्ड और सुरक्षाकर्मियों को रखने की क्या आवश्यकता है? यदि आप अपना भविष्य नहीं देख सकते, तो आप आम आदमी का भविष्य कैसे देख सकते हैं? ऐसे बाबा चांदी की कुर्सियों और सिंहासनों पर बैठकर भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं। तब बाबा राम-रहीम, आश्रम और नारायण साईं की याद आती है, जिन्होंने स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और जेल की सजा पाई। और यह स्वाभाविक है कि जब ऐसे व्यभिचारी बाबाओं को बार-बार पैरोल मिलती है, तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं। सरकार बार-बार ऐसे व्यभिचारी बाबाओं पर कड़ी नजर क्यों रखती है, जो अपराधी हैं? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अतीत में स्वामीनारायण के साधुओं पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं। तब राम रहीम, धीरेन्द्र शास्त्री और भविष्य देखने का दिखावा करने वाले अन्य साधुओं ने एक पैसा भी निवेश नहीं किया है या करने वाले नहीं हैं।

जिस प्रकार राजनेताओं को व्यापार करने के लिए धन जुटाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना पड़ता है, उसी प्रकार ये पाखंडी सनातन बाबा भी अनेक अनुयायी जुटा लेते हैं। इसलिए लोगों को ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए, और विशेषकर महिलाओं को स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों, माताओं, बहनों और बेटियों को इनसे दूर रखना चाहिए और सनातन धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के जाल में नहीं फंसना चाहिए।

ऐसे नकली बाबाओं के कारण सनातन हिंदू धर्म दिन-प्रतिदिन कलंकित होता जा रहा है। यदि हम भी सच्चे सनातन बन जाएं और ऐसे नकली बाबाओं और उन्हें सुख-सुविधाएं प्रदान करने वाले राजनेताओं का पर्दाफाश करें, तो यही सच्चे सनातनवाद का रहस्य होगा। अंत में, आइए गुरु पूर्णिमा और जन्मदिनों के बारे में बात करें। गुरु पूर्णिमा पर, सफेद बगुले के पंख धारण करके संतों के दर्शन करने आने वाले बड़े-बड़े राजनेता, शिष्य आदि महंगे उपहारों, भेंटों और नकद एवं वस्त्रों जैसे दान से नकली गुरुओं और बाबाओं की पूजा करते हैं।

इसी तरह, नेताओं के जन्मदिन पर उनके तथाकथित समर्थक उन्हें बड़े-बड़े और महंगे उपहार देते हैं और नेताओं की नज़रों में सबसे ऊपर आने की होड़ में लग जाते हैं। इस तरह भगवा और सफेद कपड़े पहनने वाले लोग बिना किसी निवेश के नकद और उपहार पा लेते हैं। वहीं, आम व्यापारी, चाहे छोटा हो या बड़ा, को अपना घर या बैंक से ऋण लेकर ही व्यापार करना पड़ता है। यह एक कड़वी सच्चाई है जहाँ एक वर्ग के पास कोई पूंजी नहीं है और दूसरा वर्ग कड़ी मेहनत करता है, फिर भी असफल हो जाता है।

अशोक खेरात ढोंगी बाबा घोटाला: महिलाओं के शोषण अंधविश्वास और राजनीतिक संबंधों का एक बड़ा खुलासा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। महाराष्ट्र के नासिक निवासी भोंडुबाबा उर्फ अशोक खेरत को आजकल राक्षस, अघोरी, व्यभिचारी, बलात्कारी, दलाल जैसे नामों से पुकारा जा रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर, उन्हें भोंडु के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ढोंगी, धोखेबाज। इस पाखंडी बाबा के खुलासे होते ही महाराष्ट्र की राजनीति और समाज में भूकंप जैसे झटके लग रहे हैं। यह पाखंडी बाबा ज्योतिष, पूजा-पाठ और समस्याओं के समाधान का काम करता था और धागे की आड़ में तथा तथाकथित निजी पूजा के नाम पर महिलाओं के कपड़े उतारता था। उसने उनमें से कुछ के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे।

सीसीटीवी में कैद उन घंटों के वीडियो से पता चलता है कि गुरुघंटाल धोंगीबाबा उर्फ अशोक खेरात महिलाओं को कुछ गतिविधियों में शामिल होने या उनके साथ सोने के लिए मजबूर करता था। वह पैसे लेकर कई लोगों के लिए कई काम करवाता था। अशोक खेरात ने ऐसा जाल बिछा रखा था कि राजनेताओं के परिवार, उच्च अधिकारियों के परिवार और उद्योगपतियों के परिवार उसके आश्रम में आते थे, जिससे समाज में यह चर्चा और फैल जाती थी कि बाबा बहुत प्रभावशाली हैं।

यह याद रखना चाहिए कि मौजूदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद, अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से नासिक के पास स्थित इस भोंदू उर्फ ढोंगी के आश्रम पहुंचे थे। वहां परिवार ने बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना की थी। उस समय की उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया से गायब हो चुकी है। तो क्या मुख्यमंत्री के इशारों पर चलने वाले एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर पूरा प्रशासनिक तंत्र और पुलिस व्यवस्था, साथ ही अधिकारी और कर्मचारी, आम जनता और भोली-भाली महिलाएं भी दब गईं? और इसी वजह से कहा जाता है कि इस बाबा ने सौ से अधिक महिलाओं का शारीरिक और आर्थिक शोषण किया है।

इस प्रकार, अशोक खेरत जैसे पाखंडी बाबाओं ने धन और दौलत कमाने के लिए यौन संबंध, शक्ति, प्रभाव, जादू आदि का इस्तेमाल किया। धन और दौलत के लालच में बाबाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा के होने से कोई समस्या असंभव नहीं थी। महिलाएं अक्सर शादी, वैवाहिक समस्याओं, संतानोत्पत्ति, संपत्ति विवाद, स्वास्थ्य, नौकरी-व्यापार आदि जैसी समस्याओं के साथ आती थीं। कई बार वे अपने भाई, पति, बहन या माता-पिता के साथ आती थीं। वे पीड़ित महिला को बाहर एक कमरे में बिठा देते थे और यह पाखंडी, जिसे कैप्टन बाबा भी कहा जाता था, उसे उस कमरे से जुड़े दूसरे कमरे में ले जाता था और अनुष्ठानों के नाम पर उसके साथ यौन संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता था। इतना ही नहीं, उसका दावा था कि यौन संबंध बनाने पर ही उसकी समस्या का समाधान होगा। ये सभी यौन क्रियाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती थीं। फिर, डर के मारे महिला को चुप रहने के लिए कहा जाता था। और इस तरह उन्होंने राजनेताओं, उच्च अधिकारियों और उद्योगपतियों की पत्नियों, बहनों और बेटियों से लाखों रुपये लूटे महाराष्ट्र और नासिक जिले में ऐसे कामी बाबा के तीन सौ से अधिक वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन वीडियो में कैद महिलाओं की निजता, गरिमा और सम्मान को बनाए रखना जरूरी है। सरकार ने यह कदम उन्हें समाज में तिरस्कृत होने से बचाने के उद्देश्य से उठाया है। साथ ही, यह नेताओं के लिए भी फायदेमंद है। अगर कोई नेता इसमें फंस जाता है, तो उसे बचाया जा सकेगा। इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने वीडियो साझा करने के आरोप में लगभग डेढ़ से दो सौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अगर हम इस नजरिए से देखें तो बाबा के अपराध बेहद गंभीर हैं। और अगर पुलिस और एसआईटी की जांच में ये बात सामने आती है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस बाबा के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है।

ये पाखंडी दिन में संतों के वस्त्र पहनते हैं, गले में तिलक, तपक और माला पहनते हैं, और रात में शराबखानों, शराब की पार्टियों, चिकन पार्टियों जैसी शैतानी हरकतें करते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। लोग ऐसे पाखंडियों से ताबीज, नींबू, मिर्च, मंत्र, तंत्र, अनुष्ठान आदि प्राप्त करके खुद को भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए, जनहित में कार्यरत सामाजिक सेवा संगठन विकास ग्राहक सुरक्षा एवं अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से सार्वजनिक रूप से निवेदन करता है कि वे ऐसे पाखंडियों को, चाहे वे किसी भी राज्य में हों, बेनकाब करें और विदेशों की तरह उन्हें कड़ी सजा दें, उनके खिलाफ मजबूत एफआईआर दर्ज करें और उन्हें फांसी पर चढ़ाएं। यदि सरकार इससे बचकर भागती है, तो सरकार को इनका सामना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि सरकार सोशल मीडिया पर महिलाओं के अश्लील वीडियो नहीं हटाती है, तो उनके परिवार और समाज उन्हें तिरस्कार की नजर से देखेंगे। यदि सरकार द्वारा ऐसे अश्लील वीडियो नहीं हटाए जाते हैं, तो जनहित में कार्यरत सामाजिक सेवा संगठन विकास ग्राहक सुरक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) भी दायर की जाएगी। अंततः, समाचार पत्रों और टीवी में मंत्रों, तंत्र और दोरा धागे के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना और लोगों को अंधविश्वास के चंगुल में फंसने से बचाना सरकार का दायित्व है।

स्वच्छता के दावे पर सवाल: सूरत के सिंगनपोर में कचरे का संकट, लोगों की सेहत और व्यवस्था दोनों पर खतरा

सूरत। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी पहचान बना चुके सूरत में इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। जहां एक ओर शहर को आधुनिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कतारगाम जोन के सिंगनपोर इलाके से सामने आई तस्वीरें इस दावे की हकीकत बयां कर रही हैं। यहां स्थित सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन के आसपास कचरे के बढ़ते ढेर ने न केवल स्थानीय लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है, बल्कि स्वास्थ्य और ट्रैफिक दोनों मोर्चों पर संकट खड़ा कर दिया है।

वेड रोड पर स्थित इस ट्रांसफर स्टेशन के पास लंबे समय से कचरे का जमावड़ा लगा हुआ है। शुरुआत में सीमित क्षेत्र तक सिमटा यह कचरा अब धीरे-धीरे फैलते हुए सड़क तक पहुंच गया है। स्टेशन की दीवार से सटे कचरे के ढेर अब खुले में फैलकर न केवल बदबू फैला रहे हैं, बल्कि सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों के लिए भी बड़ी बाधा बन गए हैं। जैसे-जैसे वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, कचरा और अधिक फैलता जाता है, जिससे स्थिति दिन-ब-दिन और गंभीर होती जा रही है।

स्थानीय निवासियों के लिए यह समस्या अब केवल असुविधा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़े स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। खुले में पड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध ने आसपास के माहौल को दूषित कर दिया है। मक्खियों और मच्छरों की बढ़ती संख्या ने बीमारियों के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। लोग आशंका जता रहे हैं कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं।

इस स्थिति का एक और गंभीर पहलू ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा प्रभाव है। सड़क पर फैले कचरे के कारण वाहनों की गति धीमी हो जाती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है। खासतौर पर व्यस्त समय में यहां से गुजरना लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है। राहगीरों को भी इस रास्ते से गुजरते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बदबू और गंदगी के बीच से होकर निकलना पड़ता है।

गौर करने वाली बात यह है कि सूरत नगर निगम हर साल शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन पर करोड़ों रुपये खर्च करता है। इसके बावजूद इस तरह की स्थिति सामने आना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। केवल बजट आवंटन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी की भी उतनी ही जरूरत होती है। सिंगनपोर का यह मामला नगर निगम के मॉनिटरिंग सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े करता है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि कचरे को समय पर उठाने और उचित तरीके से निपटान करने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कई नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि समय रहते ध्यान दिया गया होता, तो समस्या इतनी गंभीर नहीं बनती।

यह मुद्दा केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे शहर के लिए एक चेतावनी है। यदि स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध शहर में इस तरह की लापरवाही सामने आती है, तो इससे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी समस्याओं के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। स्वच्छता केवल एक अभियान या पुरस्कार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तत्काल स्तर पर कचरे के ढेर को हटाकर क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, वहीं दीर्घकालिक रूप से कचरा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है, ताकि वे भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग कर सकें।

कुल मिलाकर, सिंगनपोर में बढ़ता यह कचरा संकट सूरत की स्वच्छ छवि पर एक दाग की तरह उभर रहा है। यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि स्वच्छता बनाए रखना एक सतत जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज करने की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से करता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और शहर की स्वच्छता की पहचान बरकरार रह सके।

डगमगाते विदेशी मुद्रा भंडार: वैश्विक दबावों के बीच भारत की आर्थिक मजबूती की नई परीक्षा

नई दिल्ली। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह आई तेज गिरावट ने आर्थिक हलकों में चिंता की लहर पैदा कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.28 अरब डॉलर घटकर 688.05 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले वाले सप्ताह में भी 11.413 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे यह 698.346 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया था। लगातार दो सप्ताह की इस भारी गिरावट ने यह संकेत दे दिया है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रा बाजार में चल रही उथल-पुथल का असर अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है।

यदि हालिया रुझानों पर नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। 27 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उस समय यह माना जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अस्थिरता के बावजूद मजबूती से खड़ी है, लेकिन इसके बाद से लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। एक महीने के भीतर ही भंडार में करीब 40 अरब डॉलर से अधिक की कमी आना इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों यानी एफसीए में आई कमी को माना जा रहा है। आरबीआई के अनुसार, एफसीए में 6.622 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह घटकर 551.072 अरब डॉलर रह गया है। दरअसल, एफसीए केवल डॉलर में ही नहीं होता, बल्कि इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राएं भी शामिल होती हैं। जब इन मुद्राओं के मूल्य में डॉलर के मुकाबले उतार-चढ़ाव होता है, तो इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार के कुल मूल्यांकन पर पड़ता है। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और अन्य मुद्राओं में कमजोरी ने इस गिरावट को और तेज कर दिया है।

इसके अलावा, स्वर्ण भंडार के मूल्य में आई गिरावट भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर सामने आई है। देश के स्वर्ण भंडार में 3.666 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई, जिससे यह घटकर 113.521 अरब डॉलर रह गया है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले कीमतों में बदलाव का सीधा असर भारत के स्वर्ण भंडार के मूल्य पर पड़ता है। हालांकि, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 18.649 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत की आरक्षित स्थिति भी बढ़कर 4.816 अरब डॉलर हो गई है, लेकिन ये बढ़ोतरी कुल गिरावट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट केवल आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत भी है। अमेरिका में ब्याज दरों में बदलाव, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में सुस्ती जैसे कई कारक एक साथ मिलकर इस स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। जब वैश्विक निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और अन्य देशों की मुद्राओं पर दबाव बनता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक को अपनी मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ता है, जिससे भंडार में कमी आती है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व केवल आयात-निर्यात संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक निवेशकों के भरोसे का भी एक बड़ा संकेतक होता है। जब भंडार मजबूत होता है, तो यह संकेत देता है कि देश किसी भी बाहरी झटके को झेलने में सक्षम है।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 7166 रुपये, चांदी वायदा में 12621 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 1409 रुपये का ऊछाल

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 27 मार्च से 2 अप्रैल के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1355485.90 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 303015.49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1052462.22 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 35825 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 40114.44 करोड़ रुपये का हुआ।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 303015.49 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1052462.22 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 197401.82 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35825 पॉइंट के स्तर पर

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 197401.82 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 144000 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 154500 रुपये और नीचे में 143652 रुपये पर पहुंचकर, 142514 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 7166 रुपये या 5.03 फीसदी बढ़कर 149680 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 5094 रुपये या 4.46 फीसदी की तेजी के संग 119312 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 642 रुपये या 4.49 फीसदी की मजबूती के साथ 14935 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी मई वायदा 142190 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 152680 रुपये और नीचे में 142158 रुपये पर पहुंचकर, 6900 रुपये या 4.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 148140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 143000 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 153100 रुपये और नीचे में 142239 रुपये पर पहुंचकर, 141547 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 6992 रुपये या 4.94 फीसदी की तेजी के संग 148539 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 224247 रुपये के भाव पर खूलकर, 243981 रुपये के उच्च और 221209 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 219874 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12621 रुपये या 5.74 फीसदी के ऊछाल के साथ 232495 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 11279 रुपये या 5.03 फीसदी बढ़कर 235645 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 11360 रुपये या 5.06 फीसदी की तेजी के संग 235759 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 17901.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 16.2 रुपये या 1.42 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1155.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 13.35 रुपये या 4.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 323.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 18.2 रुपये या 5.41 फीसदी बढ़कर 354.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 2.8 रुपये या 1.45 फीसदी की बढ़त के साथ 195.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 87626.79 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 8867 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 10640 रुपये के उच्च और 8820 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1409 रुपये या 15.66 फीसदी की मजबूती के साथ 10408 रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1404 रुपये या 15.6 फीसदी की तेजी के संग 10403 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 278.8 रुपये के भाव पर खूलकर, 291.9 रुपये के उच्च और 262.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 281.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 17.1 रुपये या 6.08 फीसदी लुढ़ककर 264 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 17.2 रुपये या 6.12 फीसदी औंधकर 264 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 1018.5 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 22.4 रुपये या 2.22 फीसदी की तेजी के संग 1029.4 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 136275.43 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 61126.39 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 11803.08 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3925.80 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 135.11 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2037.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 68566.23 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 18801.70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 6648 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 30171 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 15567 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 192646 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 30575 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5778 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 13696 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 49856 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15669 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 36613 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 34417 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 36965 के उच्च और 34395 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 1536 पॉइंट बढ़कर 35825 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

मरम्मत के बहाने जहर का कारोबार: सूरत में AC मैकेनिक बना ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा, क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा

सूरत। हीरा और टेक्सटाइल नगरी के रूप में पहचान रखने वाला सूरत एक बार फिर अपराध की एक चौंकाने वाली घटना के कारण सुर्खियों में है। इस बार मामला न केवल अवैध ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा है, बल्कि इसके पीछे अपनाया गया तरीका भी उतना ही हैरान करने वाला है। गोपीपुरा इलाके में AC रिपेयरिंग के काम की आड़ में मेफेड्रोन (MD) जैसे खतरनाक ड्रग्स का धंधा चलाया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश सूरत क्राइम ब्रांच ने एक सटीक कार्रवाई के जरिए किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि अब अपराधी पारंपरिक तरीकों से हटकर आम जिंदगी के पेशों को ढाल बनाकर अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं।

क्राइम ब्रांच को इस अवैध गतिविधि की जानकारी गुप्त सूत्रों के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए गोपीपुरा के मोमनावाड स्थित जलाराम अपार्टमेंट में छापा मारा। फ्लैट नंबर 201 में की गई इस कार्रवाई के दौरान जो कुछ सामने आया, उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद हुई, जो आमतौर पर युवाओं के बीच तेजी से फैल रही एक खतरनाक सिंथेटिक नशीली पदार्थ है।

पुलिस द्वारा जब्त की गई 214.730 ग्राम MD ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 6.44 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, ड्रग्स की बिक्री में इस्तेमाल होने वाला डिजिटल तराजू, दो मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। कुल मिलाकर लगभग 6.59 लाख रुपये का सामान पुलिस के कब्जे में लिया गया है। यह बरामदगी इस बात का संकेत देती है कि यह कोई छोटा-मोटा धंधा नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से संचालित नेटवर्क का हिस्सा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद जुबैर गुलामरसुल शाह के रूप में हुई है, जिसने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वह पहले AC और फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन इस काम से होने वाली कम आय के कारण उसने करीब दो साल पहले इस अवैध कारोबार की ओर रुख कर लिया। यह बदलाव केवल एक व्यक्ति के जीवन का मोड़ नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और आर्थिक दबाव की भी झलक देता है, जो कुछ लोगों को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देता है।

जांच के दौरान आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे यह ड्रग्स शाहपुर निवासी एज़ाज़ उर्फ बटला मुश्ताक डायर से मिलती थी, जो इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक बड़ा गिरोह हो सकता है, जो शहर के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय है और छोटे-छोटे एजेंटों के माध्यम से अपने कारोबार को चला रहा है।

इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आरोपी अपने पुराने AC रिपेयरिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल ड्रग्स सप्लाई के लिए कर रहा था। यानी जिन घरों और दुकानों में वह पहले मरम्मत के काम के लिए जाता था, वहीं संपर्क अब ड्रग्स की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस एंगल ने जांच एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे यह संभावना बनती है कि यह नेटवर्क शहर के कई इलाकों में फैला हो सकता है और कई अन्य लोग भी इससे जुड़े हो सकते हैं।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी से मिले इनपुट के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि ड्रग्स की सप्लाई किन-किन क्षेत्रों में की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। जिस तरह से आम पेशों की आड़ में इस तरह के अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, वह कानून-व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। इसके साथ ही, यह भी जरूरी हो जाता है कि लोग अपने आसपास हो रही गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

कुल मिलाकर, सूरत में सामने आया यह मामला यह दिखाता है कि ड्रग्स का खतरा अब केवल सीमित क्षेत्रों तक नहीं रहा, बल्कि यह धीरे-धीरे समाज के हर वर्ग और हर इलाके में अपनी पैठ बना रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के साथ-साथ समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस खतरे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस जहर से बचाया जा सके।

टिकट की जंग में उफान: सूरत नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा में दावेदारों की भीड़, सियासी तापमान चरम पर

सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे शहर की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट पाने की होड़ ने इस बार सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहर के वार्ड नंबर 1 से 30 तक की 120 सीटों के लिए पिछले तीन दिनों में 2,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश कर यह साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला केवल विपक्ष से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर भी बेहद कड़ा होने वाला है। इस अभूतपूर्व संख्या ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जहां हर दावेदार अपने अनुभव, समर्पण और जनसंपर्क के आधार पर टिकट पाने की उम्मीद लगाए बैठा है।

आगामी नगर निगम चुनाव 26 अप्रैल को प्रस्तावित हैं और 8 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में टिकट वितरण से पहले का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी द्वारा दावेदारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से तीन दिनों में पूरा किया गया, जिसमें अलग-अलग वार्डों के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग दिन बुलाकर उनकी दावेदारी दर्ज की गई। 1 अप्रैल को वार्ड 1 से 12, 2 अप्रैल को वार्ड 13 से 24 और 3 अप्रैल को वार्ड 25 से 30 तक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऑब्जर्वर्स के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन तीन दिनों के दौरान पार्टी कार्यालयों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां समर्थकों के साथ पहुंचे दावेदार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए।

यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें हर दावेदार ने अपने-अपने तरीके से नेतृत्व को प्रभावित करने की कोशिश की। कोई अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का हवाला दे रहा था, तो कोई संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और वर्षों की सेवा को सामने रख रहा था। कई नए चेहरे भी इस बार मैदान में उतरे हैं, जो युवा नेतृत्व के नाम पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवार चयन की परंपरा को गंभीरता से निभाया जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी तय है कि अंतिम सूची में जगह बनाना आसान नहीं होगा।

दावेदारी प्रक्रिया के समाप्त होते ही अब पार्टी के भीतर चयन की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। इसके तहत सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, जो सुबह से लेकर देर रात तक चल रही हैं। इन बैठकों में प्रत्येक दावेदार के राजनीतिक अनुभव, जनाधार, संगठन में सक्रियता और जीतने की क्षमता जैसे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सूरत प्रभारी और क्षेत्रीय महासचिव डॉ. प्रशांत कोराट, सांसद मुकेश दलाल और प्रभु वसावा सहित कई वरिष्ठ नेता इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी और अन्य पदाधिकारी भी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार टिकट वितरण में किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक वार्ड में एक सीट के लिए तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। यह पैनल आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, जहां से अंतिम नामों पर मुहर लगेगी। इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की पात्रता की भी गहन जांच की गई है। खास तौर पर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले दावेदारों को सूची से बाहर कर दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी इस बार युवा और ऊर्जावान नेतृत्व को प्राथमिकता देना चाहती है।

इस पूरी कवायद के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, वह है गुटबाजी और अंदरूनी प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। इतनी बड़ी संख्या में दावेदारों के सामने आने से यह तय है कि टिकट नहीं मिलने पर असंतोष भी उभर सकता है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह सभी दावेदारों को संतुष्ट रखने की रणनीति बनाए, ताकि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की अंदरूनी कलह सामने न आए।

सूरत की राजनीति में नगर निगम चुनाव का विशेष महत्व है, क्योंकि यह केवल स्थानीय स्तर का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए भी एक संकेतक माना जाता है। भाजपा लंबे समय से सूरत नगर निगम पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है और इस बार भी वह इसे बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं, विपक्षी दल भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है।

कुल मिलाकर, सूरत नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा में टिकट को लेकर मची यह होड़ इस बात का संकेत है कि चुनावी रणभूमि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब सबकी नजरें पार्टी द्वारा घोषित की जाने वाली अंतिम उम्मीदवार सूची पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि इस बार किसे मैदान में उतरने का मौका मिलेगा और किसे इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, वैसे-वैसे सूरत की राजनीति का तापमान और भी बढ़ने की पूरी संभावना है।

संदिग्ध मौतों से दहला पूर्वी चंपारण: बीमारी, जहरीली शराब या लापरवाही-सवालों के घेरे में पूरा मामला

पटना/मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित बालगंगा गांव में बीते दो दिनों के भीतर हुई तीन संदिग्ध मौतों ने पूरे इलाके में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। बुधवार रात से शुक्रवार सुबह के बीच घटित इन घटनाओं ने न केवल स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगभग 15 लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटनाक्रम की तेजी और लक्षणों की समानता ने इस पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

मृतकों में प्रमोद यादव (32), चंदू कुमार (22) और परीक्षण मांझी (55) शामिल हैं, जिनकी मौत अलग-अलग समय पर हुई, लेकिन सभी में कुछ समान लक्षण पाए गए। बताया जा रहा है कि प्रभावित लोगों को अचानक तेज सिरदर्द, उल्टी और आंखों की रोशनी में कमी जैसी समस्याएं हुईं, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इन लक्षणों ने डॉक्टरों और प्रशासन को इस ओर संकेत दिया है कि मामला सामान्य बीमारी का नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई जहरीला तत्व या संक्रमण भी हो सकता है।

स्थानीय परिजनों ने इस घटना को जहरीली शराब से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चल रहा है और संभवतः उसी के सेवन से यह घटनाएं हुई हैं। हालांकि, पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है और पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक किसी भी कारण की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। इस बीच एक चौकीदार को निलंबित किए जाने की खबर भी सामने आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासन इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि यदि यह मामला जहरीली शराब से जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क हो सकता है, जिसे पूरी तरह से खत्म करना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं और प्रभावित गांव में विशेष निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टरों की टीम मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक दवाएं एवं उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में भर्ती सात मरीजों का इलाज जारी है, जबकि अन्य लोग निजी क्लीनिकों में भी उपचार ले रहे हैं। जिन मरीजों की हालत गंभीर है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर करने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को भी उजागर कर दिया है। शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से न लेना और समय पर उचित उपचार न मिल पाना भी कई बार ऐसी घटनाओं को और घातक बना देता है। यदि प्रारंभिक स्तर पर ही मरीजों को सही चिकित्सा सहायता मिल जाए, तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। यही कारण है कि प्रशासन अब इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सक्रिय और सतर्क बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया है। साथ ही, लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि वे किसी भी अवैध या संदिग्ध पदार्थ के सेवन से बचें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

फिलहाल, पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार मौतें हुई हैं और एक ही तरह के लक्षण सामने आए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई भारी पड़ सकती है। प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा।

कुल मिलाकर, पूर्वी चंपारण की यह घटना न केवल एक स्थानीय त्रासदी है, बल्कि यह एक बड़ी चेतावनी भी है कि अवैध गतिविधियों और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के घातक परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि इन मौतों के पीछे असली कारण क्या था और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

विकास की रफ्तार बरकरार: सूरत में पेड FSI से नगर निगम को मजबूत सहारा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने दिखाया दम

सूरत। देश के तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल सूरत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यहां विकास की रफ्तार केवल दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंकड़ों में भी साफ दिखाई देती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मंदी की चर्चाओं के बीच सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पेड फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) से होने वाली आय लगातार तीसरे साल 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शहर में निर्माण गतिविधियां अब भी मजबूती के साथ जारी हैं। यह उपलब्धि न केवल नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि सूरत के शहरी विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की निरंतरता को भी दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम ने पेड FSI से 1040 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले 1004.37 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की गई। यह लक्ष्य का लगभग 96.57 प्रतिशत है, जो किसी भी आर्थिक दृष्टिकोण से एक मजबूत प्रदर्शन माना जाता है। खास बात यह है कि पिछले दो वर्षों में भी यह आय 1000 करोड़ रुपये के पार रही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई एक बार की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्थायी प्रवृत्ति बन चुकी है।

ऑक्ट्रॉय व्यवस्था समाप्त होने के बाद नगर निगमों की आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार की ग्रांट पर निर्भर हो गया था। ऐसे में सूरत नगर निगम के लिए पेड FSI आय एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्तंभ के रूप में उभरी है। इस आय ने न केवल निगम को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं। यही कारण है कि सूरत में सड़क, जल निकासी, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

इस दौरान सेंट्रल सिटी डेवलपमेंट विभाग की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। कुल 707 डेवलपमेंट परमिशन फाइलों को मंजूरी दी गई, जिनमें 256 ऑफलाइन और 451 ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने से कार्यों की गति में तेजी आई है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। इनमें से 286 परियोजनाओं को बिल्डिंग यूसेज सर्टिफिकेट (BUC) जारी किया जाना इस बात का संकेत है कि कई प्रोजेक्ट अब पूर्णता की ओर बढ़ चुके हैं और उनका उपयोग शुरू हो चुका है।

इसके अलावा, 2400 प्लॉट वैलिडेशन फाइलों को मंजूरी मिलना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है और इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर में नए निर्माण कार्यों के लिए जमीन की उपलब्धता और योजना दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ी है। टाउन प्लानिंग विभाग की सिफारिशों के आधार पर जारी इन प्रमाणपत्रों से नगर निगम को 8 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि प्राप्त हुई है, जो भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस अतिरिक्त भूमि का उपयोग सड़कों के विस्तार, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा। नगर निगम के नए कमिश्नर एम. नागराजन के कार्यभार संभालने के बाद विकास कार्यों में और तेजी देखने को मिली है। पिछले दो महीनों में ही 172 डेवलपमेंट परमिशन फाइलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 50 ऑफलाइन और 142 ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक तेज और प्रभावी बनाया गया है। साथ ही, 679 प्लॉट वैलिडेशन आवेदनों का निपटारा कर 1.67 लाख वर्ग मीटर भूमि प्राप्त करना यह साबित करता है कि नगर निगम न केवल आय बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, बल्कि शहर के समग्र विकास के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

इन सभी आंकड़ों को यदि समग्र रूप से देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि सूरत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किसी भी प्रकार की सुस्ती का असर व्यापक स्तर पर नहीं पड़ा है। बल्कि, योजनाबद्ध विकास और प्रशासनिक दक्षता के कारण यह सेक्टर अब भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। पेड FSI से होने वाली आय ने नगर निगम को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, जिससे वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा पा रहा है।

कुल मिलाकर, सूरत का यह मॉडल अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां स्थानीय निकाय अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पेड FSI आय के माध्यम से सूरत ने यह दिखा दिया है कि यदि योजना, क्रियान्वयन और निगरानी सही तरीके से की जाए, तो शहरी विकास की रफ्तार को बनाए रखना पूरी तरह संभव है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सूरत इस गति को किस तरह और आगे ले जाता है और अपने विकास के नए आयाम कैसे स्थापित करता है।

पश्चिम एशिया संकट की मार: सूरत का टेक्सटाइल हब दबाव में, उत्पादन घटा और लागत ने तोड़ी कमर

सूरत। वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का असर अब सीधे भारत के औद्योगिक केंद्रों पर दिखाई देने लगा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण सूरत का विशाल कपड़ा उद्योग है, जो इन दिनों गंभीर आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने कच्चे माल, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स की लागत को बढ़ा दिया है, जिसके चलते सूरत की टेक्सटाइल इकाइयों को अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करना पड़ रहा है। हालात इतने चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं कि कई फैक्ट्रियों ने अपने काम के घंटे घटा दिए हैं, जबकि कुछ ने सप्ताह में काम करने के दिनों को ही कम कर दिया है।

उद्योग से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, इस संकट का सीधा असर उत्पादन और आय पर पड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सूरत का टेक्सटाइल सेक्टर इस समय रोजाना करीब 90 से 100 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रहा है। यह आंकड़ा केवल आर्थिक क्षति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी बताता है कि यह संकट कितनी गहराई तक उद्योग को प्रभावित कर रहा है। सूरत, जो देश में मानव निर्मित कपड़े के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां इस तरह की गिरावट एक गंभीर संकेत है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इकाइयों के कामकाजी दिनों को सप्ताह में सात से घटाकर पांच दिन कर दिया है। इसका उद्देश्य बढ़ती लागत को नियंत्रित करना और उत्पादन को इस तरह संतुलित करना है कि उद्योग पूरी तरह ठप न हो जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र वक्तानिया के अनुसार, कच्चे माल और कोयले की कीमतों में तेजी से वृद्धि ने उद्योग की लागत संरचना को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे संचालन करना बेहद मुश्किल हो गया है।

दूसरी ओर, फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जिरावाला ने बताया कि कई इकाइयों ने अपने उत्पादन चक्र को भी घटा दिया है। जहां पहले फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती थीं, अब उन्हें 12 घंटे तक सीमित करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है और कुल उत्पादन लगभग आधा रह गया है। पहले जहां प्रतिदिन करीब सात करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता था, अब यह आंकड़ा काफी घट चुका है, जिससे बाजार में आपूर्ति और कीमत दोनों प्रभावित हो रही हैं।

इस संकट को और गहरा बनाने वाला एक बड़ा कारण श्रमिकों की कमी है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, मजदूरों की संख्या में करीब 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले कुछ हफ्तों में 2,000 से अधिक प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गृह राज्यों की ओर लौट चुके हैं। इस पलायन के पीछे एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी और बढ़ती जीवनयापन लागत को मुख्य कारण माना जा रहा है। जब मजदूर ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो उत्पादन को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कच्चे माल की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है। मानव निर्मित फाइबर और अन्य आयातित सामग्री की कीमतों में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि ने उद्योग की लागत को और अधिक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोयले और ऊर्जा की लागत भी बढ़ी है, जिससे उत्पादन खर्च कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में उत्पाद की कीमत बढ़ाने की भी सीमाएं हैं, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा और मांग की स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों—बुनाई, प्रसंस्करण और व्यापार—तीनों पर इस संकट का असर साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कामकाज में 25 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। यह केवल उत्पादन में कमी नहीं है, बल्कि इससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए यह स्थिति और भी कठिन है, क्योंकि उनके पास बड़े उद्योगों की तरह वित्तीय सुरक्षा नहीं होती।

हालांकि, इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच उद्योग को आने वाले शादी के मौसम से कुछ उम्मीदें हैं। पारंपरिक रूप से इस समय कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन और बिक्री में सुधार हो सकता है। लेकिन यह राहत कितनी स्थायी होगी, यह काफी हद तक वैश्विक परिस्थितियों और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर निर्भर करेगा। सरकार भी इस स्थिति को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने हाल ही में सूरत में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर श्रमिकों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने मजदूरों के लिए पांच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया है, जिससे पलायन को रोका जा सके और उद्योग को राहत मिल सके।

कुल मिलाकर, सूरत का टेक्सटाइल उद्योग इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां वैश्विक संकट और स्थानीय चुनौतियां मिलकर इसे प्रभावित कर रही हैं। हालांकि, उद्योग की मजबूत बुनियाद और मांग की संभावनाएं यह संकेत देती हैं कि यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तो यह सेक्टर फिर से तेजी से उभर सकता है। लेकिन फिलहाल, यह दौर उद्योग के धैर्य, रणनीति और अनुकूलन क्षमता की कड़ी परीक्षा ले रहा है।